डि-रेगुलेशन के दूसरे चरण के सुधारों से प्रदेश में व्यापार और होगा आसान

केंद्र सरकार के उच्चस्तरीय पैनल का लखनऊ दौरा

मुख्य सचिव के साथ ईओडीबी सुधारों पर विस्तृत मंथन

लखनऊ। उत्तर प्रदेश ने डि-रेगुलेशन और कम्प्लायंस रिडक्शन के क्षेत्र में देशभर में पहला स्थान हासिल कर अपनी निवेश-अनुकूल छवि को और मजबूत किया है। कैबिनेट सचिवालय द्वारा जनवरी 2026 में जारी रैंकिंग में यूपी को डि-रेगुलेशन 1.0 के तहत शीर्ष स्थान मिला है। अब राज्य सरकार फेज-2.0 सुधारों के माध्यम से व्यापार सुगमता बढ़ाने, अनुपालनों को कम करने और निवेश प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है।

इसी क्रम में शुक्रवार को भारत सरकार के उच्चस्तरीय पैनल ने लखनऊ का दौरा किया। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व यूपी के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस टास्क फोर्स की प्रमुख सदस्य एवं एनसीबीसी की सचिव मीता राजीव लोचन ने किया। उनके साथ कैबिनेट सचिवालय के अपर सचिव राहुल शर्मा भी मौजूद रहे। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य सचिव एसपी गोयल के साथ बैठक कर सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ईओडीबी फेज-2.0 सुधारों पर ओरिएंटेशन सत्र किया।

बैठक में डि-रेगुलेशन के अगले चरण के रोडमैप पर विस्तार से चर्चा हुई। शाम को इन्वेस्ट यूपी कार्यालय में उद्योग संगठनों के साथ कम्प्लायंस रिडक्शन एवं डि-रेगुलेशन 2.0 पर संवाद हुआ, जिसमें सीआईआई, फिक्की, एसोचैम और अन्य प्रमुख उद्योग निकाय शामिल हुए। ब्यूरो